

मुख्य समाचार

- 1- निर्वाचन आयोग की सभी राज्यों और केन्द्रीय एजेन्सियों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक आज, कानून और व्यवस्था को लेकर चल रही तैयारियों की होगी समीक्षा।
- 2- राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अबतक लगभग 78 लाख रुपए हो चुके हैं बरामद, सभी चेकनाकों पर चौबीस घंटें चल रहा वाहन चेकिंग अभियान।
- 3- झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में सड़क जाम और ट्रैफिक सिस्टम पर जताई नाराजगी, ट्रैफिक एसपी आज अदालत में सशरीर उपस्थित होकर देंगे जवाब।
- 4- राज्य में सभी सरकारी विद्यालय एक-दूसरे से किए जाएंगे टैग, विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन और ड्रॉप आउट रोकने के लिए हो रही पहल।

निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरीय पदाधिकारियों तथा सीमा की रक्षा करनेवाले केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, शराब, मादक पदार्थ तथा अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम और अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अबतक विभिन्न जिलों में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अठहत्तर लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस द्वारा इसकी जांच करने के साथ आयकर विभाग को भी सूचना दी जा चुकी है। इस सिलसिले में जिनके पास से पचास हजार रुपए से ज्यादा नकद बरामद हुए हैं, उनसे उसके श्रोत की जानकारी मांगी जा रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के अंतरराज्यीय सीमाओं और अंतर जिला स्थित चेकनाका पर चौबीस घंटे वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

निर्वाचन आयोग ने झारखंड के चौदह आईएएस को विभिन्न राज्यों में इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। इन अधिकारियों में सुनील कुमार, भोर सिंह यादव, किरण कुमारी पासी, अबु इमरान और सुशांत गौरव को तमिलनाडु, फ़ैज अहमद और अभय नंदन अम्बष्ठ को महाराष्ट्र, मनोहर मरांडी, आकांक्षा रंजन और आदित्य रंजन को कर्नाटक, शशि रंजन को छत्तीसगढ़, पवन कुमार को राजस्थान, आदित्य कुमार आनंद को असम और राजीव कुमार को केरल में ऑब्जर्वर बनाया गया है।

भाजपा की प्रदेश इकाई ने सभी चौदह लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले इक्यासी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी है। विधानसभा प्रभारी के रूप में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के वरीय नेता शामिल किए गए हैं।

धनबाद जिले के उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार सामग्रियों के प्रकाशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता

साउंड बाइट— दीपक कुमार, धनबाद— 45 सेकेंड

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी
वेबसाइट [news on air.gov.in](http://news.onair.gov.in) पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

ताजा समाचार एक्स हैडल @AIR news alerts

और फेसबुक पेज All India Radio news पर भी उपलब्ध है।

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैडल

@AIR news अंडर स्कोर_ranchi

और

फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा

YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi

पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में सड़क जाम और ट्रैफिक सिस्टम पर नाराजगी जताई है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक को आज सशरीर अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने कल सुनवाई करते हुए ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक सिग्नलों की खराबी, पार्किंग व्यवस्था को लेकर नगर निगम से जवाब मांगा। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द करने की दिशा में क्या कार्रवाई हुई है। निगम द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी न्यायालय को दी गई।

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को एक-दूसरे से टैग किया जाएगा, ताकि शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के साथ बच्चों का ड्रॉप आउट रोका जा सके। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित प्ले स्कूल से लेकर प्लस टू तक के विद्यालयों को एक-दूसरे से टैग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ई-विद्या वाहिनी के वेब वर्जन में भी टैगिंग की जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी छात्र-छात्रा नामांकन से वंचित नहीं रहे इसे सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद- एनसीईआरटी ने कहा है कि पहली, दूसरी, सातवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए 33 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं। वहीं, तीसरी और छठी कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें इस महीने और अगले महीने प्रकाशित कर दी जाएंगी। यह भी कहा गया है चौथी, पांचवीं, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा की किताबें इस महीने बाजार में आ जाएंगी।

एनटीपीसी द्वारा झारखंड में बिजली और कोयला खनन के क्षेत्र में पचास हजार करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया जा चुका है। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय के सीइओ अनिमेष जैन ने बताया कि एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड, ओडिशा व छत्तीसगढ़ से रिकॉर्ड चौत्तीस मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है। इसमें झारखंड के पकरी बरवाडीह कोयला खदान से सोलह दशमलव तीन एक मीट्रिक टन, चट्टी बरियातू खदान से तीन दशमलव तीन मीट्रिक टन और केरेडारी कोयला खदान से दशमलव दो चार मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ।

राज्य की सभी अदालतों में ग्यारह मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस सिलसिले में दस मार्च से दस मई तक काउंसिलेशन बैठक होगी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालयों में मामलों को निष्पादन के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे।

जमशेदपुर के मानगो स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पैनल बोर्ड में आज सुबह आग लगने की वजह से पेयजलापूर्ति पर व्यापक असर पड़ा। हालांकि आग पर तुरन्त काबू पा लिया गया। जिस वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ।

- सीसीएल ने चतरा जिले के टंडवा में संचालित आम्रपाली और मगध कोल परियोजना के तहत जिला खनिज निधि कोष, डीएमएफटी ने पिछले एक वर्ष में एक सौ 17 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
- राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के डिबडीह में आज सवेरे एक दुकान में लाग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जल गए। फायर ब्रिगेड की टीम के आने के बाद आग पर काबू पाया गया
- गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति की एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में छह युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करार्यी गई है।
- राजधानी रांची में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के जोनल कार्यालय का कल उद्घाटन हुआ. यह कार्यालय झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड कार्यालय परिसर में है।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में सार्वजनिक प्रसारण सेवा को बेहतर बनाने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न खंडों के मुद्दों, पायरेसी से निपटने और कंटेंट सामग्री की सुरक्षा पर भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। लोग 30 अप्रैल तक इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं।
